कर्मचारियों से अधिक नहीं है और जब कभी निर्धारित घंटों से अधिक समय तक ड्यूटी देने के लिए उनकी सेवाओं की आवश्यकता होती है तो नियमों के अधीन ए० एस० आई,० हैडकान्सटेबल तथा कान्सटेबलों को भोजन भत्ता दिया जाता है। इन्हीं सीमित साधनों में यह सुनिश्चित करने की हर कोशिश की जा रही हैं कि अधिक से अधिक पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी दी जाए ।

Industries in Meghalaya

6030 SHRI P. A. SANGMA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) the number of large andmedium industries under public sector in Meghalaya;

(b) whether Government are considering to set up any large/medium scale industries under public sector in Meghalaya this Year; and

(c) if so, the number, place and nature thereof ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES) : (a) None, Sir; However, the following large and medium industries under Joint sector are in operation in Meghalaya :—

1. Cherrapunji Cement Factory.
2. Komorrah Lime Stone Ltd.
3. Meghalaya Essential Oils & Chemicals Ltd.
4. Meghalaya Phyto Chemicals Ltd.

(b) and (c). There is no such proposal at present under the consideration of the Central Government. However, the Meghalaya Industrial Development Corporation, a State Government Undertaking, is contemplating to set up the following projects in the State, under joint sector, in collaboration with other parties :—

1. Jute Mill.
2. Calcium Carbide Project.
3. Welded Wire Mesh Project.
4. Canned Meat Project.
5. Fruit Processing Project.
6. Asbestos Cement Sheets Project.
7. Mini Paper Plant.
8. Biogas & Fertiliser Project.
9. Jaintia Cement Project.
10. V-Belt and Fan Belt Project.
11. Cement Clinker Project.
12. Acetylene Black Project.
13. Sack Kraft and Insulation Paper Project.

Details regarding location of these projects are not readily available.

Cement Clinker project at Siju (Meghalaya)

6031. SHRI P. A. SANGMA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to set up a Cement Clinker Project at Siju in Meghalaya under public sector; and

(b) if so, the progress made thereof ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) Yes, Sir.

(b) The Meghalaya Industrial Development Corporation, a State Public Sector Undertaking, was granted an industrial licence in July, 1974, valid for two years, for the manufacture of 4 lakh tonnes of Cement Clinker per annum, based on the limestone deposits available in between the villages Siju Songmong and Siju Artica of Garo Hills. Part of the produce was intended to be supplied to Bangla Desh. The validity of industrial licence was extended for a further period of one year i.e. up to 30-7-1977, at the request of the Corporation to enable it to implement the project. No request for further extension of time has been received as yet.

Radio Station at Tura in Meghalaya

6032. SHRI P. A. SANGMA : will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether there was any proposal to set up a Radio Station at Tura in Maghalaya; and

(b) if so, the steps taken so far ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) Yes, Sir.

(b) A provision for setting up a radio station at Tura was included in the original shelf of schemes for the draft Fifth Plan. However, due to the paucity of financial resources, this provision could not be retained in the finalised version of the Fifth Plan. The area has been surveyed from the point of view of ascertaining the feasibility of setting up a radio station at this centre. Frequencies have also been coordinated internationally for the operation of medium-wave transmitters at Tura. Attempt will be made to include it in the 6th Plan proposals.

पर्वतीय क्षेत्रों के लिये योजना

6033. **श्री बालक राम :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोगौलिक और जलवायु की दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्रों के कृषि तथा औद्योगिक विकास हेतु देश के मैदानी क्षेत्रों के लिए बनाई गई योजनाओं से भिन्न योजना की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है और उससे हिमाचल प्रदेश कितनी मात्रा में लाभान्वित हुआ है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) पर्वतीय क्षेत्रों वाली राज्य सरकारों या पूर्णत: पर्वतीय राज्यों से यह अनुरोध किया गया हैं कि कृषिक तथा अन्य विकास कार्यक्रम तैयार करते समय वे अपने अधिकार-क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों की प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति, संसाधन प्रयास, आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था, आदि का ध्यान रखें ।

मुख्य उद्देश्य ये हैं कि कृषि, बागबानी, वनोद्योग और भूमि संरक्षण के विकास कार्य को व्यापक किया जा सके । अर्थ-व्यवस्था के कृषि तथा अन्योन्य क्षेत्रों के विकास में तीव्रता लाने के लिए बिजली, सिंचाई, सड़क, विपणन तथा ऋण से संबंधित बुनियादी आधारभूत सुविधाओं को बढाया जा सके । व्यापक विषमताओं को कम करने/समाप्त करने के लिए प्राथमिक शिक्षा, पेयजल की पूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण स्वास्थ्य आदि से संबंधित कार्यक्रमों पर भी बल दिया गया है ।

पर्वतीय राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की प्रणाली अधिक उदार हैं । इस प्रणाली से हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर को भी लाभ मिलता है ।

जो राज्य आंशिक रूप से पर्वतीय हैं वे स्थानीय स्थलाकृति, कृषि-जलवायु की स्थिति और संसाधनों के अनुरूप अपने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग से उप योजनाएं तैयार करते हैं । इन उप योजनाओं को कार्यान्वित करने के उनके प्रयासों में सहयोग करने के लिए उन्हें विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

शिमला अथवा कसौली में दूरदर्शन केन्द्र

6064. **श्री बालक राम :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के दूरदराज के इलाकों के लिए शिमला अथवा कसौली में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों तथा हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरजोर मांग की है ।

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए किन-किन मार्गदर्शी बातों का पालन किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवानी : (क) जी, हां ।